



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13—जनवरी 19, 2018 (पौष 23, 1939)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13—JANUARY 19, 2018 (PAUSA 23, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	5	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	17	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	45	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 33
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 29
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	5	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	17	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	45	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	33
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	29
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

सं. 5/12/2016-चमड़ा—केंद्र सरकार ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2,600 करोड़ रुपए के अनुमोदित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना 'भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी)' का कार्यान्वयन शामिल है।

2. इस योजना से चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान, अतिरिक्त निवेश की सुविधा, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि होगी।

3. 2017-18 से 2019-20 के दौरान आईएफएलएडीपी के तहत निम्नलिखित उप-योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी :—

- (i) मानव संसाधन विकास (एचआरडी)
- (ii) चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस)
- (iii) संस्थागत सुविधाओं की स्थापना
- (iv) मेगा लेदर, फुटवियर और सहायक सामग्री क्लस्टर (एमएलएफएसी)
- (v) चमड़ा प्रौद्योगिकी, अभिनवीकरण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे
- (vi) चमड़ा, फुटवियर और सहायक सामग्री क्षेत्र में भारतीय ब्रांडों का संवर्धन
- (vii) चमड़ा, फुटवियर और सहायक सामग्री क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन

4. उपर्युक्त सात उप-योजनाओं के दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट <http://dipp.nic.in/programmes-and-schemes/others/indian-leather-development-programme> पर उपलब्ध हैं।

5. आईएफएलएडीपी के तहत उप-योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एक अधिकार प्राप्त समिति और एक संचालन समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

6. अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

- (i) भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी।
- (ii) भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न उप-योजनाओं के दिशा-निर्देशों में संशोधन का सुझाव देना और चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित/अनिवार्य विशिष्ट उपायों का सुझाव देना।
- (iii) चमड़ा उद्योग से संबंधित अथवा उनसे जुड़े विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी का समन्वय एवं संकलन करना और चमड़ा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी संबंधितों को उसका प्रसार करना।

- (iv) संचालन समिति को प्रदत्त शक्तियों अधिकारों के अलावा भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम की उप-योजनाओं के तहत प्रस्तावों को मंजूरी देना।
- (v) संबंधित दिशा-निर्देशों में उल्लिखितानुसार भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम की सभी उप-योजनाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को मंजूरी देना।
- (vi) किसी भी अन्य मुद्दे को शामिल करना जो ऊपर नहीं दिया गया है।

7. समिति अपनी प्रक्रियाओं को विकसित करेगी और एक या एक से अधिक उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है या इस पर विचार कर सकती है। यह समय-समय पर और आवश्यकतानुसार बैठक करेगी।

8. अधिकार प्राप्त समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

(i)	सचिव (आईपीपी)	अध्यक्ष
(ii)	वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	सदस्य
(iii)	अपर सचिव (चमड़ा), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	सदस्य
(iv)	नीति आयोग का प्रतिनिधि जो सलाहकार की रैंक के नीचे न हो	सदस्य
(v)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक के नीचे न हो	सदस्य
(vi)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो	सदस्य
(vii)	वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो	सदस्य
(viii)	एमएसएमई के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो	सदस्य
(ix)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो	सदस्य
(x)	अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद	सदस्य
(xi)	अध्यक्ष, फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री परिषद	सदस्य
(xii)	अध्यक्ष, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान	सदस्य
(xiii)	प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान	सदस्य
(xiv)	निदेशक, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान	सदस्य
(xv)	राज्य से संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधि जिसके लिए भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है	विशेष आमंत्रित व्यक्ति
(xvi)	संगठन का प्रतिनिधि जिसके लिए भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है	विशेष आमंत्रित व्यक्ति
(xvii)	प्रस्ताव पर विशेषज्ञता वाले संगठन के विशेषज्ञों जिनके लिए भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत विचार किया जा रहा है	विशेष आमंत्रित व्यक्ति
(xviii)	संयुक्त सचिव (चमड़ा), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	संयोजक
(xix)	अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अन्य आमंत्रित व्यक्ति	विशेष आमंत्रित व्यक्ति

9. संचालन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

- (i) प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, कार्यप्रणालियों को निर्धारित करना, आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक मानक संयंत्र और मशीनरी के लिए नियामक कीमतों का निर्णय करना, सरकार से वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त करना और उप-योजना चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) के तहत औद्योगिक इकाईयों के लिए सरकार से वित्तीय सहायता की निगरानी तथा संवितरण करना।

- (ii) भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 'चमड़ा प्रौद्योगिकी, अभिनवीकरण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे' की उप-योजना के मानव संसाधन विकास तथा सामान्य बहिष्साव आशोधन संयंत्र संघटक की उप-योजनाओं के तहत 15 करोड़ रु. तक की लागत वाले प्रस्तावों का अनुमोदन और
- (iii) भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- (iv) संबंधित दिशानिर्देशों में उल्लिखितानुसार आईएफएलएडीपी की सभी उप-योजनाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना।
- (v) अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सौंपा गया अन्य कोई भी कार्य।

10. समिति अपनी प्रक्रियाओं को विकसित करेगी और एक या एक से अधिक उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है या इस पर विचार कर सकती है। यह समय-समय पर और आवश्यकतानुसार बैठक करेगी।

11. संचालन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :—

(i)	संयुक्त सचिव (डीआईपीपी)	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक/उप सचिव (वित्त विंग), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
(iii)	वाणिज्य विभाग के नामिति	सदस्य
(iv)	एमएसएमई मंत्रालय के नामिति	सदस्य
(v)	निदेशक, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा नामिति	सदस्य
(vi)	प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अथवा नामिति	सदस्य
(vii)	संवितरण बैंक (बैंकों) के मुख्य महाप्रबंधक अथवा नामिति	सदस्य
(viii)	अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद	सदस्य
(ix)	अध्यक्ष, फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री परिषद	सदस्य
(x)	निदेशक/उप सचिव (चमड़ा), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	संयोजक
(xi)	अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अन्य आमंत्रित व्यक्ति	विशेष आमंत्रित व्यक्ति

पी दासगुप्ता
उप सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

विषय: परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2018 से आगे बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (1)—सरकार द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I के तहत प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें समय-समय पर बढ़ाया गया था । इन प्रावधानों को इस बीच 31 दिसम्बर 2017 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2018 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ईश्वर शरण
अवर सचिव

विषय: यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2018 से आगे बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (2)—सरकार द्वारा यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I के तहत प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें समय-समय पर बढ़ाया गया था । इन प्रावधानों को इस बीच 31 दिसम्बर 2017 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2018 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ईश्वर शरण

अवर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

अनुपूरक संकल्प

सं. ई.—11012/2/2015—हिंदी—भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी दिनांक 25 मई, 2015 के संकल्प में एतद्वारा क्रम सं. 21 के सामने निम्नलिखित नाम अंतःस्थापित किया जाता है :—

21. डॉ. डी. पी. त्रिपाठी, संसद सदस्य (राज्य सभा), 13—डी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली—110001 सदस्य

स्थायी पता : —डॉ. डी. पी. त्रिपाठी, संसद सदस्य (राज्य सभा), बी—105, अकांशा टावर, पंच मार्ग, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई—400053

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. के. मिश्रा
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 21st December 2017

No. 5/12/2016-Leather—The Central Government has approved a special package for employment generation in leather and footwear sector. The package includes implementation of Central Sector Scheme 'Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme (IFLADP)' with an approved expenditure of Rs. 2600 crore over the three financial years from 2017-18 to 2019-20.

2. The scheme would lead to development of infrastructure for the leather sector, address environment concerns specific to the leather sector, facilitate additional investments, employment generation and increase in production.

3. The following sub-schemes would be implemented under IFLADP during 2017-18 to 2019-20 :—

- (i) Human Resource Development (HRD)
- (ii) Integrated Development of Leather Sector (IDLS)
- (iii) Establishment of Institutional Facilities
- (iv) Mega Leather, Footwear and Accessories Cluster (MLFAC)
- (v) Leather Technology, Innovation and Environmental Issues
- (vi) Promotion of Indian Brands in Leather, Footwear and Accessories Sector
- (vii) Additional Employment Incentive for Leather, Footwear and Accessories Sector.

4. The guidelines of above mentioned seven sub-schemes are available on the website of the Department i.e. <http://dipp.nic.in/programmes-and-schemes/others/indian-leather-development-programme>.

5. In order to ensure effective implementation of the sub-schemes under IFLADP, it has been decided to constitute an Empowered Committee and a Steering Committee.

6. The Terms of Reference of the Empowered Committee will be as under :—

- (i) Monitor the implementation of Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme.
- (ii) To suggest modifications in the guidelines of the various sub-schemes under Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme and also suggest specific measures required/essential to achieve the desired output for the development of the leather sector.
- (iii) To co-ordinate and collate information about schemes being implemented by various Ministries/Department having connection or linkage to leather industry and synergize/disseminate the same to all concerned for overall development of the leather sector.
- (iv) Approve proposals under the sub-schemes of Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme beyond the delegated powers of the Steering Committee.
- (v) Approve specific issues concerning all sub-schemes of Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme as mentioned in the concerned guidelines.
- (vi) To take up any other issue not specified above.

7. The Committee will devise its own procedures and may appoint one or more Sub-committees, as it may consider. It will meet from time to time and as per requirement.

8. The composition of the Empowered Committee will be as under :—

(i)	Secretary (IPP)	Chairman
(ii)	Financial Adviser, Department of Industrial Policy and Promotion	Member
(iii)	Additional Secretary (Leather), Department of Industrial Policy and Promotion	Member
(iv)	Representative of NITI Ayog not below the rank of Adviser	Member
(v)	Representative of Ministry of Environment, Forests and Climate Change not below the rank of Joint Secretary	Member
(vi)	Representative of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation not below the rank of Joint Secretary	Member

(vii)	Representative of Department of Commerce not below the rank of Joint Secretary	Member
(viii)	Representative of Ministry of MSME not below the rank of Joint Secretary	Member
(ix)	Representative of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship not below the rank of Joint Secretary	Member
(x)	Chairman, Council for Leather Exports	Member
(xi)	Chairman, Council for Footwear, Leather and Accessories	Member
(xii)	Chairperson, Footwear Design and Development Institute	Member
(xiii)	Managing Director, Footwear Design and Development Institute	Member
(xiv)	Director, Central Leather Research Institute	Member
(xv)	Representative of State Government pertaining to the State for which the proposal under Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme is being considered	Special Invitee
(xvi)	Representative of the organization for which the proposal under Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme is being considered	Special Invitee
(xvii)	Experts from organization having expertise on the proposal under Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme is being considered	Special Invitee
(xviii)	Joint Secretary (Leather), Department of Industrial Policy and Promotion	Convener
(xix)	Other Invitees as decided by the Chairman	Special Invitee

9. The Terms of Reference of the Steering Committee will be as under :—

- (i) Ensure effective implementation, lay down procedures, decide normative prices for standard plant and machineries required for the modernization programme, accord sanction of financial assistance from Government, and monitor and follow up disbursement of financial assistance from Government to the industrial units under the sub-scheme Integrated Development of Leather Sector (IDLS);
- (ii) Approval of proposals under the sub-schemes of Human Resource Development and Common Effluent Treatment Plant component of 'Leather Technology, Innovation and Environmental Issues' sub-scheme under Indian Footwear, Leather and Accessories Development Programme costing upto Rs. 15 crore; and
- (iii) Monitor the implementation of the projects sanctioned by the Department under Indian Footwear, Leather and Accessories Development Programme.
- (iv) Resolve specific issues concerning all sub-schemes of IFLADP as mentioned in the concerned guidelines.
- (v) Any other work assigned by the Empowered Committee.

10. The Committee will devise its own procedures and may appoint one or more Sub-committees, as it may consider necessary. It will meet from time to time and as per requirement.

11. The composition of the Steering Committee will be as under :—

(i)	Joint Secretary (DIPP)	Chairman
(ii)	Director/Deputy Secretary (Finance Wing), Department of Industrial Policy and Promotion	Member
(iii)	Nominee of Department of Commerce	Member
(iv)	Nominee of Ministry of MSME	Member
(v)	Director, Central Leather Research Institute or nominee	Member
(vi)	Managing Director, Footwear Design & Development Institute or nominee	Member
(vii)	Chief General Manager of Disbursing Bank (s) or nominee	Member
(viii)	Chairman, Council for Leather Exports	Member
(ix)	Chairman, Council for Footwear, Leather and Accessories	Member
(x)	Director/Deputy Secretary (Leather), Department of Industrial Policy and Promotion	Convener
(xi)	Other Invitees as decided by the Chairman	Special Invitee

P DASGUPTA
Deputy Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 26th December 2017

Sub : Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2018.

No.1/61/2004-Exports-I (1)—The Government, vide Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2017.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2018.

3. All other terms and conditions mentioned in Para 1 of the Notification dated 9th November, 2004 shall remain unchanged.

ISHWAR SHARAN
Under Secretary

Sub : Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2018.

No.1/61/2004-Exports-I (2)—The Government, vide Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2017.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2018.

3. All other terms and conditions mentioned in Para 1 of the Notification dated 9th November, 2004 shall remain unchanged.

ISHWAR SHARAN
Under Secretary

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 20th December 2017

SUPPLEMENTARY RESOLUTION

No. E-11012/2/2015 Hindi—In the Resolution dated 25 May, 2015 regarding reconstitution of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Civil Aviation the following name is hereby inserted against the serial No. 21.

- | | | |
|----|--|--------|
| 21 | Shri D.P. Tripathi, Member of Parliament (Rajya Sabha), 13-D,
Ferozshah Road, New Delhi-110001

Permanent Address:- Dr. D. P. Tripathi, Member of Parliament (Rajya Sabha),
B-105, Akansha Tawar, Panch Marg, Andheri West, Mumbai | Member |
|----|--|--------|

ORDER

Ordered that a copy of this Supplementary Resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. MISHRA
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2018
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2018

www.dop.nic.in